Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding forceful eviction of people from the lands they have been living their in Nagaur Constituency, Rajasthan.

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज सुबह लॉटरी के अंदर हम सबका नाम था और हम अनुपस्थित हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी आपने शाम के समय हम सबको बोलने का मौका दिया है । मैं आपका ध्यान आज़ादी से पूर्व और जिनको अभी 100 साल से भी ज्यादा बसे हुए हो गए हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं । गोचर भूमि, अंगूर भूमि और दूसरे जो भूमिहीन लोग हैं, जिन्होंने वहां पर प्रधान मंत्री आवास बना लिए हैं, इंदिरा गांधी आवास के नाम से जो योजना चली थी, उसमें भी बना लिए हैं । उन्होंने बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, रोड्स भी बन गई हैं । उन आबादियों को राज्य सरकार और राजस्व विभाग कई जगहों से हटा रहा है । कोई जाकर दावा अपील करता है, कभी रेवेन्यू बोर्ड हटा देता है, तो कभी कलेक्टर के यहां से आदेश हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर बंजारा, रेबारी, गाडीया, लुहार, ओबीसी और एसबीसी सहित कई जातियां इससे पीड़ित हैं । मैं एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूं । मैं नागौर जिले के ताउसर समीप राजस्व ग्राम रामनाडा में बसी हुई बंजारा बस्ती की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । इन बस्तियों में आज़ादी के पहले से सैकड़ों परिवार रह रहे हैं, जो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हैं । यहां पीएम आवास, आंगनबाड़ी से लेकर राशन कार्ड तक बने हुए हैं । इसी तरह का मामला बीकानेर जिले के नोखा के पास साटिका के अंदर है । यहां पहले कलेक्टर के आदेश से तोड़-फोड़ हुई थी, नुकसान हुआ और हम लोग मौके पर पहुंचे थे । उन लोगों ने हाई कोर्ट की भी शरण ली है । उन लोगों ने जमीनें भी राज्य सरकार को समर्पित कर दी हैं । सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे कई फैसले हैं, जिनके अंदर यह कहा गया है कि अगर किसी गांव के अंदर गोचर भूमि है, गोचर में आबादी बस गई है और

वह डिस्टर्ब होती है, तो उसके बदले में वह लोग दूसरी जमीन खातेदारी की देते हैं, तो उसको सेट अपार्ट कर दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, इन बंजारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय राजस्थान की सरकार कर रही है । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप राजस्थान सरकार को निर्देशित करें । जहां प्रधान मंत्री आवास बन गए, जहां उनके राशन कार्ड बन गए, जहां गोत्र भूमि के अंदर स्कूल बन गए, वहां उसके बदले वे सरकार को जमीन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बेदखल किया जा रहा है ।

महोदय, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । यह पूरे देश की समस्या है । यह मेरे इलाके की समस्या है, इसलिए मैंने कोट किया है । कल मैं आपसे व्यक्तिगत मिलकर गया था और आपने इसके लिए मुझे मौका भी दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता हूं कि सरकार, राज्य सरकरों को निर्देशित करे कि अगर कोई जमीन के बदले जमीन दे रहा है और वह सौ वर्ष से ज्यादा से बसा हुआ है तो उन व्यक्तियों को न उजाड़ें । हमें उनको बचाने का काम करना है, उजाड़ने का काम नहीं करना है । प्रधान मंत्री जी का जो संदेश है, वह राज्यों की सरकारों तक जाना चाहिए । मेरा यह निवेदन है कि बंजारों को न्याय मिले ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि लिस्ट निपट गई है और आज 8 बजे तक सदन चलाना है । अगर सभी माननीय सदस्य एक-एक मिनट में अपनी सीट पर जाकर बोलेंगे तो सदन के अंदर उन माननीय सदस्यों को हम बोलने का मौका दे देंगे । जो एक मिनट से ज्यादा बोलेगा, घण्टी बजाकर दूसरे माननीय सदस्य को मौका दे दिया जाएगा । एक मिनट वाले ही तैयार रहें, बाकी दो मिनट वाले कल बोलें ।